

यकण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रजिस्ट्रार संख्या एक
द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थाई विधेयाज्ञा का दाव प्रेष किया गया
बाद के साथ याज्ञा पर अन्ततः धारा 212 राजस्थान कानूनकारी

परत की है।

कानूनकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 30 जून 2019 को
2019 के विभाग आगत अधीन अधीन अदागत हाना के समक्ष राजस्थान
हजूमालसिंह व नाम किशोरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 जून
अधिकारी अधिनियम द्वारा राज्य विधेयाज्ञा पर संख्या 198/2019
अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपायुक्त
दिनांक : 17 नवंबर 2021

निर्णय

श्री राजेश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रज. संख्या दो
श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता रज. संख्या एक
श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता-अधीनस्थ
उपस्थित-

----- 0 -----

अधीन अन्ततः धारा 225 राजस्थान कानूनकारी
अधिनियम, 1955 बख्तगाफ आदेश सहायक
कलेक्टर एवं उपायुक्त अधिकाारी, अधिनियम दिनांक
01 जून 2019 राज्य विधेयाज्ञा पर संख्या
198/2019 हजूमालसिंह व नाम किशोरसिंह इत्यादि
रज. संख्या ...



- 01. हजूमालसिंह व नाम किशोरसिंह वी, जति राजपूत,
जिवासी- श्रीमसागर, तहसील अधिनियम, जिला जोधपुर।
- 02. तहसीलदार अधिनियम, जिला जोधपुर।

म

न

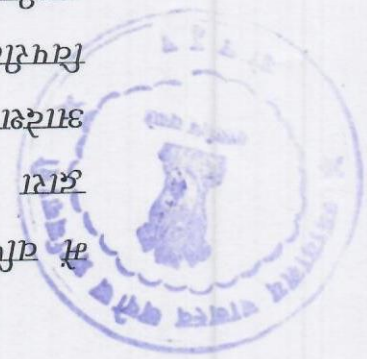
व

अधीनस्थ ...

किशोरसिंह व नाम किशोरसिंह, जति राजपूत, जिवासी- श्रीमसागर,
तहसील अधिनियम, जिला जोधपुर।

(Handwritten mark)

परतुत किया गया है। अब मैं अधीनकार के अधिवक्ता ने निवेदन किया
गया, जिसमें राजकुंकर अधीनकार को परेशान करने की विषय से दावा
बदलियाति से प्रत्यक्ष द्वारा अधीनकार न्यायालय में दावा परतुत किया
संश्लिष्ट किसे जाने का निवेदन किया, जिसकी जानकारी होने पर
तस्मीम किसे जाने का निवेदन किया तथा आदेश दिनांक 15.12.1992 को
मौके की स्थिति के विषय है, इसलिए मौके की स्थिति की जांच कर
द्वितीय जोधपुर के समक्ष अधीन परतुत की कि जारी नवशा मौके पर
बंदाडा दिनांक 15.12.1992 के विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता जिला कलक्टर
आगौच्य आदेश पारित किया है, जो अपारत योज्य है। अधीनकार को
की जा सकती है। उपरोक्त विधि के सिद्धांत की अनदेखी करते हुए
विधि के सिद्धांत कि सद्व्यवहार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं
अपारत व निरस्त किसे जाने योज्य है। अधीनकार न्यायालय द्वारा इस
आदेश, आदेश 39 सीपीसी के प्राधान्यों के विषय होने के कारण भी
संहिता के प्राधान्यों की प्राधान्य किसे ब्यौर ही आदेश पारित किया है जो
अधीनकार न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश जारी किसे जाने के प्रस्ताव
विषय होने के कारण अपारत व निरस्त किसे जाने योज्य है।
आदेश पारित किया है जो आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के
द्वारा नोटिस जारी किसे विना ही एकपक्षीय बहस चलते हुए आगौच्य
में पूर्ण विंगुओं को दखते हुए कथन किया कि अधीनकार न्यायालय
बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अधीनकार ने तथ्यों एवं अधीन मामलों



बढ़े।

आदेश पारित कर दिये गये, जिसके विरुद्ध आगौच्य अधीन परतुत की
के खास नं. 801/12 रकबा 18.07 बीघा के मौके की यथास्थिति के
बीघा खास नं. 127/10 रकबा 14.19 बीघा तथा नाम जायदों की दाणी
विवादित भूमि नाम भूमिसार के खत खास नं. 123/7 रकबा 12.18
रेप्रीजेंट संख्या एक को एकपक्षीय सुनकर दिनांक 01 जुलाई 2019 को
अधिवक्ता का परतुत किया, जिस पर अधीनकार न्यायालय द्वारा

[Handwritten signature]

समाप्त होना है।

व्यापार्य द्वारा पारित अंतरिम आदेश अदागत होना की राय में
समाप्त रूप से उभय पक्ष के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ
प्रशासक द्वारा, स्थिति का संतुलन एवं अप्रत्याशित क्षति के विरुद्ध
रेगुलेशन द्वारा समाप्त के रेगुलेशन का रेगुलेशन है। इसीलिए
18.07 बीमा की ऑनलाइन रसीदों को जारी है। अधीनस्थ एवं
19 बीमा तथा नाम वास्तु की जारी के खसरा नं. 801/12 रकबा
खसरा नं. 123/7 रकबा 12.18 बीमा खसरा नं. 127/10 रकबा 14.
रकबा रेगुलेशन के मुआवजा वारंटों को जारी नाम अधीनस्थ के खसरा
39 सीपीसी की पंजीयन जारी किया जाना था है। अतः
अंतरिम आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ आदेश में आदेश
के अधीनस्थ मुआवजा वारंटों को जारी किया जाये। अधीनस्थ के
को मुआवजा का अंतरिम रसीदों द्वारा रेगुलेशन संख्या एक को
01 जुलाई 2019 को पंजीयन पर नं. रेगुलेशन किया जाकर अधीनस्थ
रेगुलेशन पूर्वक अधीनस्थ व्यापार्य द्वारा विना
वृत्त पर भरोसा किया गया एवं उपलब्ध अधीनस्थ का अधीनस्थ



के अंतर्गत अधीनस्थ विभागाध्यक्ष पारित किया जाये। अधीनस्थ के
विना संश्लेष अधीनस्थ नं. एक को नं. अधीनस्थ एवं अधीनस्थ

अधीनस्थ संश्लेष नं. से जारी करमाणी जाये।

संश्लेष अधीनस्थ आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों की जा रही है। अधीनस्थ व्यापार्य द्वारा रेगुलेशन को
आरंभ में रेगुलेशन संख्या एक के कब्जे का अधीनस्थ द्वारा
अधीनस्थ के कब्जे का अधीनस्थ करते हुए विना किया कि अधीनस्थ
वर्ष में रेगुलेशन संख्या एक के अधीनस्थ नं. अधीनस्थ के

विना 01 जुलाई 2019 को अधीनस्थ किया जाये।

कि अधीनस्थ अधीनस्थ करमाणी जाये तथा अधीनस्थ आदेश

रजिस्ट्रार
राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर
(जयपुर न्यायालय)

जिसे आज खले न्यायालय में सुनाया गया।
12/11/2021



उपरोक्त विवरण के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर परसपर दस्तावेजों की जाँच है तथा उक्त पक्ष को वाद के निस्तारण के पारद किया जाता है कि वे उक्त पक्ष के पक्ष-पक्षक खसरा के आदेश परसपर दस्तावेजों की जाँच है।